

एस. पी. गोयल और प्रीतपाल सिंह, जे.जे. के समक्ष
सुभाष चंद्र जैन, - याचिकाकर्ता,
बनाम
हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव
व्होलसेल स्टोर और अन्य, -प्रतिवादी।
सिविल रिट याचिका संख्या 3297 आफ 1979
फ़रवरी 26, 1986.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 12 और 226- रिट ऑफ़ मैनडेमस -सहकारी समिति-जब उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन हो।

माना जाता है कि, आम तौर पर सहकारी समितियां उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती हैं, लेकिन जब भी कोई सोसायटी किसी के पूर्वाग्रह के लिए किसी वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहती है, तो वह रिट मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का हकदार है। सोसायटी को वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन न करने का निर्देश देने का आदेश। दूसरे शब्दों में, इतने लंबे समय तक कोई मामला नहीं बनता

वैधानिक प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन, जिसका पालन करना एक सोसायटी के लिए बाध्य है, उसके खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। लेकिन जब भी यह बताया जाता है कि सोसायटी को किसी विशेष तरीके से कार्य करने की आवश्यकता वाला कोई वैधानिक प्रावधान किसी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार या हित बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सोसायटी के खिलाफ रिट का उपाय तलाशना स्वीकार्य होगा। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि सहकारी समिति केवल रिट याचिकाकर्ता में संबंधित कानूनी अधिकार बनाने वाले कानून द्वारा लगाए गए कानूनी दायित्व और कर्तव्यों के प्रदर्शन से संबंधित मामलों में रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होगी। दूसरे शब्दों में, एक सहकारी समिति केवल उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होगी, जहां कानून के प्रावधानों या अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, जिसके द्वारा सोसायटी शासित होती है, कोई वैधानिक या सार्वजनिक अधिकार है। इस पर शुल्क लगाया गया है और इसे लागू करने की मांग की जा रही है।

(पैरा 5).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई कि यह माननीय न्यायालय प्रसन्न हो: -

(i) मामले के रिकॉर्ड मंगवाएं और उसके अवलोकन के बाद, रिट याचिका के अनुलग्नक पी-10 में प्रतिवादी संख्या 2 की नियुक्ति को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट जारी करें।

(ii) सोसायटी के नियुक्ति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए रिट ऑफ़ मैनेजमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना; या वैकल्पिक रूप से प्रतिवादी नंबर 2 को पद पर बने रहने के लिए अपना कानूनी अधिकार दिखाने का निर्देश देने के लिए एक वारंट रिट, क्योंकि वह अधिनियम की धारा 84-ए के तहत बनाए गए वैधानिक सेवा नियमों के तहत अपेक्षित योग्यता को पूरा नहीं कर रहा है।

(हाय) प्रस्ताव की सूचना जारी करने और अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट दी जा सकती है।

(iv) सिविल रिट याचिका को लागत सहित अनुमति दी जा सकती है।

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका की सुनवाई लंबित होने तक, विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई जाए या वैकल्पिक रूप से प्रतिवादी नंबर 2 के कामकाज पर रोक लगाई जाए।

के.एस. कुंडू, और आर.एस. टैकोरिया, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए

उत्तर डेंट नंबर 2 के लिए प्रेम सिंह, वकील और एच. सी. राठी, वकील।

बी.एस. खोजी, वकील, प्रतिवादी 1 के लिए।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप सिंह, वीरेंद्रपाल सिंह, अधिवक्ता भी मौजूद हैं।

निर्णय

प्रितपाल सिंह, जे.

(1) लेखा अधिकारी का एक पद प्रथम प्रतिवादी-हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड, चंडीगढ़ द्वारा 10 जून, 1979 को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए विज्ञापित किया गया था। इसके लिए कई उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद निदेशक मंडल ने शुरू में श्री एस.के. नरवानिया का चयन किया लेकिन उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद, श्री वी.के. बाउंट्रा का चयन किया गया लेकिन उन्होंने भी यह पद नहीं लेने का फैसला किया। अंततः दूसरे प्रतिवादी-अवतार सिंह को प्रतीक्षा सूची से नियुक्त किया गया। वह अपेक्षित योग्यताएं पूरी नहीं करता था लेकिन रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने उसके संबंध में छूट दे दी। इस रिट याचिका में अवतार सिंह की नियुक्ति को सुभाष चंद्र जैन द्वारा चुनौती दी गई है, जो इस पद के लिए उम्मीदवारों में से एक थे, लेकिन उनका चयन नहीं किया गया था। चुनौती के आधार दो-पकड़ वाले हैं। पहला, यह कि प्रतिवादी अवतार सिंह नियुक्ति के लिए योग्य नहीं थे और दूसरा, यह कि लेखा अधिकारी का पद पदोन्नत कोटे का था और इसलिए इसे सीधी भर्ती से नहीं भरा जा सकता था।

(2) सबसे पहले विद्वान उत्तरदाताओं के वकील ने इस पर आपत्ति जताई कि रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि प्रतिवादी-सोसाइटी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिकल्पित एक वैधानिक निकाय या सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। भारत। इस तर्क के समर्थन में अजमेर सिंह बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में,¹ यह माना गया कि एक सहकारी समिति एक गैर-वैधानिक निकाय है इसके विरुद्ध रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

(3) इस निर्णय पर अंतर्निहित निर्भरता रखते हुए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-सोसाइटी केवल सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के कारण इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(4) दूसरी ओर, विद्वान याचिकाकर्ता के वकील ने कुलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य में इस न्यायालय की पिछली डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा जताया², जिसमें यह माना गया था कि एक सहकारी सोसायटी के खिलाफ रिट सुनवाई योग्य है। अगर

¹ ए.आई.आर. 1981 पंजाब और हरियाणा 107

² 1972 पी.एल.जे. 399.

(कानून द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता है। यह निर्णय प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन बनाम सी.वी. इमैनुअल और अन्य³ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है जिसमें यह कहा गया था:-

“यह साफ है कि मेंडेमस एक ऐसे कानूनी कर्तव्य की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए है जिसके प्रदर्शन करने वाले के पास एक पर्याप्त कानूनी हित होता है जिसके अनुसार वह इसके लिए आवेदन कर रहा है”

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

“इसलिए, मेंडेमस की जारी होने के लिए पूर्व-शर्त यह है कि जिसने इसका दावा किया है, उसके पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार होना चाहिए जिसका पूरा किया जाना उस व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कानूनी कर्तव्य के लिए है जिसके खिलाफ यह अनुप्रयास किया जा रहा है। मेंडेमस का आदेश, रूप में, किसी व्यक्ति, कॉर्पोरेशन या एक न्यूनतम ट्रिब्यूनल को एक ऐसी विशिष्ट चीज को करने के लिए होता है जो उनके कार्यालय में है और एक सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति है। हालांकि, आवश्यक नहीं है कि कानूनी कर्तव्य जिस पर थोपा जा रहा है, वह सार्वजनिक अधिकारी या एक आधिकारिक निकाय हो। एक मेंडेमस, उदाहरण के लिए, सोसाइटी के एक अधिकारी को जोर देने के लिए जारी किया जा सकता है ताकि उसे स्थापित या नियंत्रित करने वाले अधिनियम की शर्तों का पालन करने के लिए बाधित किया जाए और भी कंपनियों या कॉर्पोरेशन्स को जो कानूनी अधिकारों को अधिकृत करने वाले उनके अधिनियमों द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मेंडेमस जारी किया जा सकता है।”

(5) अजमेर सिंह (सुप्रा) के मामले में पूर्ण पीठ ने कुलवंत सिंह (सुप्रा) के मामले में फैसले पर गौर किया और उससे असहमत नहीं थी। पूर्ण पीठ ने पाया कि डिवीजन बेंच के फैसले का बारीकी से विश्लेषण करने से पता चलेगा कि विद्वान न्यायाधीशों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असंगत नहीं था। दोनों निर्णयों को एक साथ पढ़ने पर, कानूनी प्रस्ताव जो उभरता है वह यह है कि आम तौर पर सहकारी समितियां उच्च न्यायालय

³ एआईआर. 1969 एस.सी. आईएम

के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं होती हैं, लेकिन जब भी सोसायटी किसी के पूर्वाग्रह के लिए वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहती है, तो बाद वाला हकदार है 'दृष्टिकोण'

सोसायटी को वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन न करने का निर्देश देने के लिए मैनेजमेंस की रिट मांगने के लिए न्यायालय। दूसरे शब्दों में, जब तक वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है, जिसका अनुपालन करने के लिए एक सोसायटी बाध्य है, तब तक उसके खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। लेकिन जब भी यह बताया जाता है कि सोसायटी को किसी विशेष तरीके से कार्य करने की आवश्यकता वाला कोई भी वैधानिक प्रावधान किसी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार या हित बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सोसायटी के खिलाफ रिट का उपाय तलाशना स्वीकार्य होगा। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि सहकारी समिति केवल रिट याचिकाकर्ता में संबंधित कानूनी अधिकार बनाने वाले कानून द्वारा लगाए गए कानूनी दायित्व और कर्तव्यों के प्रदर्शन से संबंधित मामलों में रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होगी। इसे रखना। संक्षेप में, एक सहकारी समिति केवल उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होगी, जहां अधिनियम के तहत बनाए गए कानून या नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जिसके द्वारा सोसायटी शासित होती है, उस पर कोई वैधानिक या सार्वजनिक कर्तव्य लगाया जाता है। इसे और लागू करने की मांग की जा रही है।

(6) वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी-समाज के कर्मचारी हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड (इसके बाद कहा जाएगा) के कर्मचारी सेवा नियमों के रूप में जाने जाने वाले वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। 'नियम')। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि उसने स्वीकार किया कि प्रतिवादी अवतार सिंह ने सीधी भर्ती द्वारा लेखा अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया था, और जबकि उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था, प्रतिवादी अवतार सिंह को नियमों का उल्लंघन करके नियुक्त किया गया था। ऐसे में विचार करने की बात यह है कि क्या इस आरोप में कोई सच्चाई है?

(7) अनुबंध (I) के साथ पढ़ा गया नियम 6(1) यह स्पष्ट करता है कि सीधी भर्ती द्वारा लेखा अधिकारी के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार के पास दो योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले, वह प्रथम श्रेणी बी.कॉम होना चाहिए। और दूसरा, उसके पास पर्यवेक्षी क्षमता में खातों में पांच

साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को योग्यता में छूट देने के लिए पंजाब सहकारी समितियां नियम, 1963 के नियम 28 के तहत अधिकार प्राप्त है। यह नियम इस प्रकार है:-

“28(1) कोई भी सहकारी समिति किसी भी व्यक्ति को अपने कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं करेगी जब तक कि उसके पास ऐसी योग्यताएं और सुविधाएं न हों। रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई ऐसी सुरक्षा समाप्त कर देता है।

(2) रजिस्ट्रार, किसी भी मामले में, विशेष कारणों से, इस नियम के प्रावधानों को उस सीमा तक शिथिल कर सकता है, जिसे वह उचित समझे।”

(8) माना जाता है कि प्रतिवादी अवतार सिंह ने अपेक्षित योग्यताओं को सख्ती से पूरा नहीं किया, क्योंकि वह सेकेंड डिवीजन बी.कॉम है। और नियुक्ति के समय पर्यवेक्षी क्षमता में खातों में पांच साल का अनुभव नहीं था। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि रजिस्ट्रार ने उनके मामले में योग्यता के संबंध में छूट दी थी। इसके अलावा, इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा पारित छूट के आदेश की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है। रजिस्ट्रार योग्यता के मामले में छूट देने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे और उन्होंने प्रतिवादी अवतार सिंह के पक्ष में इस अधिकार का प्रयोग किया। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि अवतार सिंह की नियुक्ति योग्यता के मामले में वैधानिक नियमों का उल्लंघन है।

(9) दूसरी आपत्ति यह है कि लेखा अधिकारी का पद पदोन्नतों के कोटे से संबंधित है और इसलिए, सीधी भर्ती से नहीं भरा जा सकता है, यह भी गलत धारणा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियमों के नियम 9.4 में यह प्रावधान किया गया है कि लेखा अधिकारियों के 66 प्रतिशत पद पदोन्नत लोगों द्वारा और शेष 33 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा रखे जाएंगे। लेकिन नियमों में यह बताने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है कि इन दोनों स्रोतों से नियुक्तियां किस तरीके से की जानी हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रतिवादी-समाज को नियुक्तियाँ करते समय दोनों स्रोतों का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि परस्पर कोटा परेशान न हो। वर्तमान मामले में यह भी आरोप नहीं लगाया गया है कि जब विवादित पद विज्ञापित किया गया था तब सीधी भर्ती का कोटा पहले ही भरा जा चुका था। यह इंगित करने के लिए बिल्कुल भी कोई सामग्री नहीं है कि यह

पद आवश्यक रूप से पदोन्नति द्वारा भरा जाना था। ऐसी परिस्थितियों में यह मानना संभव नहीं है कि प्रतिवादी अवतार सिंह की नियुक्ति से नियम 9,4 की वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन किया गया है।

(10) उपरोक्त कारणों से, हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

एन.के.एस,

अस्वीकरण:

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा